सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से संबद्ध)

33, प्रभांजलि, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष : का. एन. चक्रवर्ती

महासचिव : का. डी. आर. महापात्र

परिपत्र क्र. : 09/2021

दिनांक : 24/9/2021

मध्य क्षेत्र के समस्त साथियों के नाम

विषय : सीजेडआईईए कार्यकारिणी समिति की बैठक सम्पन्न

प्रिय साथियों,

सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 19–20 सितंबर को रायपुर में संपन्न हुई बैठक की अध्यक्षता का टी.पी. पांडे द्वारा की गई। बैठक में विशेष रूप से एआईआईईए के उपाध्यक्ष व सीजेडआईईए के उपाध्यक्ष काम. बी. सान्याल उपस्थित थे। सीजेडआईईए के अध्यक्ष काम. एन. चक्रवर्ती परिवार में स्वास्थ्यगत असुविधा के कारण से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। वहीं एआईआईईए के महासचिव काम. श्रीकांत मिश्र भी अपने स्वास्थ्यगत कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए।

शोक प्रस्ताव :

बैठक के प्रारंभ में पिछली बैठक से लेकर अब तक हमने जिन साथियों को खोया उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एआईआईईए के सहसचिव एससीजेडआईईएफ के महासचिव काम. क्लेमेंट जेवियर दास, आम बीमा क्षेत्र के पश्चिम क्षेत्र के पूर्व महासचिव काम. के.सी. नटराजन, सीटू के कोषाध्यक्ष काम. रंजना निरुला, सीटू के मध्यप्रदेश के राज्यस्तरीय नेतागण काम. पी.के. डे, काम. सुबीर तालुकदार, काम. विद्याशंकर मुफलिस, फादर स्टेन स्वामी, सामाजिक कार्यकर्ता, सतारा मंडल के पूर्व महासचिव काम. सी.पी. कुलकर्णी, एलआईसी के पूर्व अध्यक्ष श्री आर. जोशी, पूर्व कार्यकारी निदेशक श्री शरद श्रीवास्तव, ओलंपिक पदक विजेता श्री मिल्खा सिंह, फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार, सिद्धार्थ शुक्ला, सुरेखा सीकरी तथा करोना के चलते विदंगत हुए एलआईसी के साथियों व उनके परिजनों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इसके बाद सीजेडआईईए के महासचिव काम. डी.आर महापात्र ने पिछली बैठक के बाद की परिस्थितियों की विस्तारपूर्ण जानकारी दी। इस दरम्यान करोना महामारी के चलते हमने हमारे मध्यक्षेत्र के नेतृत्वकारी साथियों के अलावा बहुत सारे साथियों के परिजनों को खोया है। जिसका हमें दुख है।

कार्यकारिणी समिति ने नोट किया कि प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि आपदा को अवसर में बदलो और इसका पूरा लाभ व्यवसायियों ने उठाया, चारों तरफ लूट मची थी, करोना वारियर्स के रूप में आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर आदि ने करोना पीड़ितों की सेवा की है। लेकिन इनमें से कितने लोग करोना में काम के दौरान मृत हुए उन लोगों का आंकड़ा भी सरकार के पास नहीं है। इस करोना महामारी के दौर में सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में बेच रही है। सरकार इस महामारी से निपटने में पूरी तरह से विफल रही है। इससे बचने का एकमात्र विकल्प है वैक्सीनेशन। लेकिन सरकार इसको भी पूरा नहीं कर पाई है।

पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी भारी उछाल है। आम लोगों की क्रय शक्ति में इसके कारण भारी गिरावट है। अर्थव्यवस्था वास्तव में इसके कारण मांग के संकट से गुजर रही है। यह परिस्थिति बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश और सरकारी हस्तक्षेप की मांग करती है। अमेरिका, ब्रिटेन हो या दुनिया के अन्य देश हों, उन्होंने अपनी जीडीपी के एक बड़े हिस्से को राजकीय सहायता के रूप में नगद हस्तांतरण लोगों को किया है, उदाहरणार्थ अमेरिका में जीडीपी का 27 प्रतिशत, ब्रिटेन में 17 प्रतिशत राशि नगद सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई जबकि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के द्वारा गैर आयकर दाता प्रत्येक परिवार को आगामी छह माह तक साढ़े सात हजार रुपये प्रतिमाह की नगद सहायता उपलब्ध कराने की मांग को सरकार आज भी अस्वीकार कर रही है। भारत सरकार की ओर से जिन राहत पैकेजों की घोषणा की गई वह हमारी जीडीपी

का मात्र 2 प्रतिशत है तथा वह भी केवल ऋण आधारित है। इसके जरिए भी बड़े पूंजीपतियों को ही और राहत दी जा रही है। सरकार द्वारा विगत सात वर्षों में इन्हीं बड़े पूंजीपतियों के क्षमा के 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि राईट-ऑफ यानि माफ कर दिये गये। इसी तरह दुनिया के बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की घटती कीमतों के बाद भी देश में पिछले छह माह में पेट्रोल की कीमतों में 67 बार और डीजल की कीमतों में 63 बार बढ़ोत्तरी की गई। वैसे ही गैस की कीमतों में 63 बार बढ़ोत्तरी की गई। वैसे ही गैस की कीमतें बढ़कर 950 तक पहुंच गई जबकि इस अवधि में कच्चे तेल की कीमत वर्ष 2004-05 की तुलना में सबसे न्यूनतम स्तर पर है और रसोई गैस की प्रति मीट्रिक टन कीमत 2014 के 880 डालर से घटकर 2021 में 382 डालर है। इस कमी का लाभ आम जनता को देने की बजाए भारत सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क व सेस लगाकर आम जनता की जेबों से 3.4 लाख करोड़ रुपये वसूल लिए।

कार्यकारिणी समिति ने नोट किया कि सरकार की नीतियों से जनता के बीच असमानता की खाई और गहरी हुई है। इसे संबोधित करने अपनी नीतियों में बदलाव की बजाए आपदा को अवसर में बदलने और आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकार देश की आम जनता की संपत्ति को ही निजी पूंजी की लूट के लिए उपलब्ध कराने का अभियान चला रही है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईप लाईन (एमएनपी) योजना उनकी इसी नीति का हिस्सा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने के नाम पर कोयला, ऊर्जा, दूरसंचार, रक्षा, रेल, सड़क हवाई अड्डा, परिवहन, बैंक, बीमा, अंतरिक्ष अनुसंधान, वेयर हाऊस यानि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है। सरकार ने आगामी 4 वर्षों में छह लाख करोड़ रुपये जुटाने के नाम पर सब कुछ नीलाम करने का फैसला किया है। सरकार यह प्रचार कर रही है कि वह फालतू में पड़ी या फिर अनुपयोगी साधनों को लीज पर देकर मुद्रीकरण कर साधन जुटा रही है और दीर्घकाल में देश को इसका लाभ होगा। कार्यकारिणी समिति का स्पष्ट मत था कि यह सफेद झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। असल मायने में यह विनिवेश के नाम पर महारत्न, नवरत्न जैसी मुनाफादेय सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी पूंजी की लूट के लिए उनके हाथों सौंप देना ही है। उसी तरह कृषि क्षेत्र भी बनाए गए। नये कृषि कानून इस क्षेत्र को भी कार्पोरेट्स के हवाले करने का ही प्रयास है। सरकार के द्वारा महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, छात्रों, युवाओं के जनवादी अधिकारों पर हमले और बढ़े हैं। संसद सहित देश की समस्त जनतांत्रिक संस्थाओं को बौना बना दिया गया है। पेगासस के जरिये लोगों की जासूसी और निजता पर बड़े हमले जैसे महत्वपूर्ण विषय हो या किसानों के आंदोलन, सरकार किसी भी मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार नहीं। सरकार प्रत्येक संस्थाओं और उनकी नीतियों पर प्रश्न उठाने वाले व्यक्ति हो या संस्था की आवाज को दबाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं वह लोगों की आवाज को दबाने के लिए उन पर देशद्रोह तक का आरोप लगा रही है। सरकार जनता के मूल समस्याओं पर अपनी विफलता छिपाने तथा उनकी नीतियों के खिलाफ किसानों के अभूतपूर्व संघर्ष तथा उनके साथ श्रमिक जगत की एकजुट कार्यवाहियों के साथ आम जनता की विकसित हो रही साझी एकता को कमजोर करने के लिए निम्न स्तर के सांप्रदायिक ध्रुवीयकरण का घिनौना अभियान चला रही है।

कार्यकारिणी समिति ने नोट किया कि करोना महामारी तथा अर्थव्यवस्था के संकट की चुनौती के बाद भी भारतीय जीवन बीमा निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। निगम ने 5 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी पर 34 लाख 36 हजार 6 सौ 86 करोड़ रुपये के लाइफ फंड के साथ 38 लाख 4 हजार 610 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति का निर्माण किया। ब्रांड, फाइनेंस, इंश्योरेंस 100 के सर्वेक्षण के अनुसार एलआईसी विश्व में तीसरी सबसे मजबूत और दसवीं सबसे मूल्यवान ब्रांड है।

निगम ने विगत दो वर्षों के प्रतिस्पर्धात्मक दौर के बाद भी 2.10 करोड़ नई पॉलिसियों की बिक्री तथा 1.84 लाख करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय अर्जित कर प्रीमियम हिस्से पर अपना नियंत्रण कायम रखा। निगम ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन व दावा निष्पादन के कारण 19 से अधिक पुरस्कार जीते हैं। कार्यकारिणी समिति ने इस बात पर गहरे रोष का इजहार किया कि भारत सरकार इस बेहतरीन संस्थान को कमजोर करने इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने व इसके आईपीओ जारी करने का फैसला लिया, इसके लिए सरकार ने एलआईसी एक्ट में संशोधन को वित्त विधेयक के साथ संसद में पेश किया जो पूरी तौर पर अलोकतांत्रिक है। इसका अर्थ साफ है कि सरकार संसद तक में इस पर बहस से बचना चाहती थी। सरकार को अपने ही सांसदों पर ही शायद विश्वास नहीं था क्योंकि एआईआईईए ने देश भर में हर राजनैतिक दल के सांसद के साथ भेंट कर इससे देश को होने वाले नुकसान से अवगत करा दिया था।

सरकार ने संसदीय बहुमत का दुरुपयोग कर एलआईसी एक्ट पारित कर लिया। सरकार द्वारा एलआईसी के संन्नहित (एमबेडेड वेल्यू) मूल्य निर्धारण के लिए मिलियन एडवाइजर्स को नियुक्त किया गया। समाचार जगत में छपी खबरों के अनुसार इसके लिए 10 मर्चेन्ट बैंकों की सेवाएं ली जा रही हैं। इसी तरह आय बीमा क्षेत्र में यूनाईटेड इंडिया के निजीकरण के जिबना एक्ट में संशोधन के जरिए सरकार ने संसद में आम बीमा क्षेत्र की किसी भी कंपनी में अपनी अंशधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं करने के वचन को तिलांजलि देकर आम बीमा की अन्य कंपनियों के निजीकरण का भी मार्ग प्रशस्त कर लिया।

कार्यकारिणी समिति ने सरकार के इन कदमों के खिलाफ मध्य क्षेत्र में चले अभियानों जिनमें दो-दो बार सांसदों से भेंट तथा प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री को प्रबुद्धजनों द्वारा लिखे गए पत्र, पर्चा वितरण, नुक्कड़ सभाएं, मानव श्रृंखला इत्यादि शामिल है, के लिए मध्य क्षेत्र के समस्त साथियों को बधाई दी। कार्यकारिणी समिति ने एआईआईईए सचिव मंडल के फैसलों की रोशनी में राष्ट्रीयकृत भारतीय जीवन बीमा निगम के निजीकरण के प्रयासों के खिलाफ पूरे मध्य क्षेत्र में जबर्दस्त अभियान हेतु निम्न निर्णय लिए गए। जो इस प्रकार हैं-

1. मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की राजधानियों में अक्टूबर माह में राज्य स्तरीय कन्वेंशन किए जाएंगे।
2. सभी मंडलों में इस पर न्यूनतम तीन केन्द्रों पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।
3. जनता के बीच पर्चा वितरण, नुक्कड़ सभाएं, जत्थे आदि निकाले जाएंगे।
4. सभी मंडलों में भारतीय जीवन बीमा की मजबूती तथा दावा निष्पादन व अभिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष बीमा सेवा पखवाड़ा, अभिकर्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित किए जाएं।
5. एआईआईईए के आव्हान पर एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ हड़ताल सहित अन्य आंदोलन के लिए भी तैयार रहें।

इस अभियान में समाज के प्रबुद्धजनों के साथ 'भारत के लिए लोग मंच' में शामिल प्रबुद्धजनों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

कार्यकारिणी समिति ने संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ इन अभियानों को संगठित करने का आव्हान करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को निजीकृत करने के वर्तमान सरकार के प्रत्येक कदम का डटकर मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे ढकेलने मजबूत संघर्ष संगठित करने का निश्चय किया। कार्यकारिणी समिति ने इस बात के लिए बीमा कर्मचारियों के जबर्दस्त आंदोलन की सराहना की जिसके बल पर पिछले 26 वर्षों में एलआईसी को पूंजी बाजार में ढकेलने से हम रोक पाए। इन मजबूत संघर्षों और एआईआईईए के अभियानों को मिले अभूतपूर्व जन समर्थन के दबाव के कारण ही एलआईसी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के लिए संसद में पारित प्रस्तावों के समय भारत सरकार को यह कहना पड़ा कि सरकार एलआईसी का निजीकरण नहीं करेगी। साथ ही उन्हें निगम की पॉलिसियों पर सरकार की सार्वभौम गारंटी को भी जारी रखना पड़ा है। कार्यकारिणी समिति ने इस पूरे अभियान को संचालित करने की प्रक्रिया में भारतीय जीवन बीमा निगम को मजबूत बनाने बीमाधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध ट्रेड यूनियन की उपस्थिति से आश्वस्त करते हुए '*एलआईसी है तो कहीं और क्यों*' के नारे के साथ उन्हें अपने भरोसे को कायम रखने के लिए प्रेरित करने तथा देश की उन्नति के लिए एक मजबूत स्तंभ बन चुके एलआईसी की रक्षा के लिए समर्थन जुटाने का अभियान संगठित करने का फैसला लिया।

अत्यंत विषम परिस्थितियों के बावजूद एआईआईईए के शानदार कौशल के चलते हमने 15 अप्रैल 2021 को बेहतरीन वेतन पुनर्निर्धारण को प्राप्त करने में सफलता हासिल की। कार्यकारिणी समिति ने पुनः एक बार ऐतिहासिक वेतन पुनर्निर्धारण के लिए एआईआईईए को बधाई दी। मध्य क्षेत्र में लेव्ही कलेक्शन का कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया तथा साथियों ने संपूर्ण उत्साह के साथ एआईआईईए के आव्हान पर इस सांगठनिक कार्य को निर्धारित समय पर पूर्ण कर लिया। कार्यकारिणी समिति ने साथियों से आव्हान किया कि अब हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है इस ऐतिहासिक वेतन पुनर्निर्धारण की हिफाजत करना। कार्यकारिणी समिति ने मध्यक्षेत्र में अभी भी जिन मंडलों में इस मद में जो राशि बकाया है उसे तत्काल प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया।

कार्यकारिणी समिति ने केंद्र सरकार के नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ मजदूरों और किसानों के व्यापक आंदोलन के साथ संपूर्ण एकजुटता का इजहार करते हुए 27 सितंबर को किसानों द्वारा

आयोजित भारत बंद के आव्हान के समर्थन में भोजनावकाश के दौरान मध्यक्षेत्र में द्वार प्रदर्शन आयोजित करने का आव्हान किया एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के बीच सभी स्तर पर एकता कायम कर संयुक्त अभियान संगठित करने का भी निर्णय लिया गया। कार्यकारिणी समिति ने 2 अक्टूबर 2021 को भोपाल में मध्यप्रदेश स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र की हिफाजत हेतु आयोजित कन्वेंशन में सभी मंडलों से न्यूनतम कुछ साथियों को शामिल कराने का निर्णय लिया। इसमें भोपाल मंडल के अधिकतम साथी शामिल होंगे।

कार्यकारिणी समिति की बैठक में मध्यक्षेत्र में इस अवधि में विभिन्न मंडलों द्वारा चलाये गए अभियानों व आंदोलनों की भी समीक्षा की गई। 1 सितंबर के मानव श्रृंखला, 4 अगस्त को आम बीमा कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में एकजुट कार्यवाहियां, 23 जुलाई व 26 जुलाई 2021 को निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियन के संयुक्त आंदोलनों, नवनियुक्त सहायकों के लिए ट्रेड यूनियन कक्षा का आयोजन आदि सभी कार्यक्रमों को मध्यक्षेत्र में शानदार ढंग से संचालित करने के लिए मध्यक्षेत्र के समस्त साथियों को बैठक ने बधाई दी। कार्यकारिणी समिति ने आगामी दिनों के अभियानों को सफल बनाने की अपील की।

कार्यकारिणी समिति ने संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा के बाद निम्न निर्णय लिए –

1. सभी मंडलों में वार्षिक विवरण समय पर भेजे जाएं तथा अन्य जरूरी सांगठनिक दस्तावेज नियमित रूप से आद्यतन किये जाएं।
2. आंदोलन की खबर व इंश्योरेंस वर्कर के नवीनीकरण का कार्य समय पर पूर्ण किया जाए तथा इनके विज्ञापन हेतु निर्धारित राशि तथा माह में ही इसे प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. सभी मंडलों में ट्रेड यूनियन शिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं।
4. कार्यकारिणी समिति ने सीजेडआईईए सचिव मंडल में काम. स्वर्णेन्दु दास तथा कार्यकारिणी समिति में काम. विजय उपाध्याय को शहडोल मंडल से सदस्य के रूप में सर्वसम्मति को–ऑप्ट किया।
5. कार्यकारिणी समिति ने रायपुर में सीजेडआईईए के स्वयं के भवन निर्माण का सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार कर इस कार्य हेतु काम. अलेक्जेण्डर तिर्की, काम. व्ही.एस. बघेल, काम. बी.के. ठाकुर व काम. सुरेन्द्र शर्मा की चार सदस्यीय समिति का गठन किया।
6. कार्यकारिणी समिति ने मौजूदा परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए संगठन में प्रत्येक स्तर पर सांगठनिक और विचाराधात्मक हर स्तर पर प्रत्येक किस्म की कमजोरियों को दूर कर संगठन की एकता को सुनिश्चित करने और समय की मांग के अनुरूप संगठन को संगठित करने पर जोर दिया।
7. कार्यकारिणी समिति ने सभी मंडलों में काम. एन.एम. सुंदरम स्मृति अध्ययन समूह को तत्काल प्रारंभ कर संगठन के पत्र–पत्रिकाओं, परिपत्रों आदि के पठन–पाठन का कार्य प्रारंभ किये जाने पर जोर दिया।

बैठक में कर्मचारियों से संबंधित लंबित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई।

साथियों, निश्चय ही बीमा कर्मचारियों ही नहीं सम्पूर्ण मेहनतकश जनता के लिहाज से वर्तमान दौर भारत सरकार की कार्पोरेटपरस्त एवं विभाजनकारी सांप्रदायिक आक्रामक नीतियों के चलते सबसे प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण है। निश्चित ही बीमा कर्मचारी हो या देश की मेहनतकश जनता उनके पास इन परिस्थिति का मुकाबला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं क्योंकि एक ट्रेड यूनियन के रूप में हम परिस्थितियों का निर्माण नहीं करते बल्कि उपलब्ध प्रतिकूल परिस्थितियों में बदलाव के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए हमारे पास चुनौतियों को चुनौती देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हमें विश्वास है कि मध्य क्षेत्र के बीमा कर्मचारी इसी विश्वास के साथ एआईआईईए और सीजेडआईईए के उपरोक्त सभी आव्हानों को पूरी क्षमता के साथ सफल बनाने एकजुट होंगे।

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ...

आपका साथी

(डी.आर. महापात्र)

महासचिव ■